भुखमरी को मिटाना आवश्यक

डॉ. वाई. पी. गुप्ता

आजकल भुखमरी से मौत की खबरें देश के एक या दूसरे भाग से आ रही हैं। इससे पता चलता है कि हमारा सार्वजनिक वितरण तंत्र ठीक से कार्य नहीं कर रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार देश में लगभग 70 लाख बच्चे प्रति वर्ष भूख से मरते हैं।

जुलाई 2009 में हमारे खाद्य भंडार की स्थिति लगभग 500 लाख टन थी जो इस वर्ष के लिए काफी है। परन्तु 2009-10 में खाद्यान्न उत्पादन मानसून वर्षा की कमी के कारण कम होने का अनुमान है जिससे खाद्य भंडार की स्थिति खराब हो सकती है।

हमारी आबादी में एक तिहाई लोग इतने गरीब हैं कि वे भोजन प्राप्त करने में असमर्थ हैं। और देश में भूखे लोगों की संख्या बढ़ रही है। राष्ट्र संघ खाद्य व कृषि संगठन (एफएओ) की रिपोर्ट के अनुसार देश में भूखे लोगों की संख्या 22.1 करोड़ है। गरीबी को कम करने की सरकार की कई योजनाएं कागज़ों पर ही रह गई हैं और इनका लाभ ज़रूरतमंद लोगों को नहीं पहुंचा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ लोग बढ़ती गरीबी के कारण गंभीर कदम उठा रहे हैं। आन्ध्रप्रदेश के पालुगु टन्डा क्षेत्र के आदिवासी, जिनके पास कोई काम नहीं है, अपने बच्चों को बेचने की अपील कर रहे हैं क्योंकि वे उनकी देखभाल नहीं कर सकते। गरीबी को कम करने की योजनाओं पर कार्य बहुत आवश्यक है।

आज विकासशील देशों में भूखे लोगों की संख्या बढ़ती आबादी के साथ बढ़ रही हैं। पिछले पांच सालों में विश्व में भूखे लोगों की संख्या 1.8 करोड़ बढ़ी। विश्व जनसंख्या जनवरी 2009 में 6.75 अरब हो गई है और वर्ष 2030 तक अनुमानित 8.9 अरब आबादी को खिलाने के लिए आज से दुगनी अधिक कैलोरी की आवश्यकता होगी। भारत की आबादी 2008-09 में बढ़ कर 115.4 करोड़ हो गई है जो 2007-08 में 113.8 करोड़ थी।

पिछले दो दशकों में खाद्यान्न उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि के बावजूद विश्व के गरीब देशों में प्रतिदिन भूखे सो जाने वाले लोगों की संख्या एक अरब से अधिक है। इसका मुख्य कारण गरीबी है। कुछ समय पहले उत्तरी कोरिया में पांच लाख लोग भुखमरी से मरे थे। इण्डोनेशिया में भुखमरी से 450 बच्चे प्रतिदिन मर जाते हैं। वैसे एफ.ए.ओ. का अनुमान है कि दुनिया में कुपोषितों की संख्या 2015 में 57.5 करोड़ और 2030 में 40.0 करोड़ तक घट जाएगी।

पहले यह अनुमान था कि वर्ष 2020 तक भारत गरीबी और कुपोषण से मुक्त हो जाएगा और पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित हो जाएगा। इस समय देश में 22.1 करोड़ लोग अल्पपोषित हैं और 36.0 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। 50 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं में खून की कमी है और देश में प्रत्येक तीसरा बच्चा कम वज़न का पैदा होता है, जिससे असंतुलित स्वास्थ्य और दिमाग के विकास का जोखिम रहता है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, यदि सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार न हुआ तो भारत 2015 तक गरीबी कम नहीं कर सकेगा।

विश्व खाद्य सम्मेलन, रोम में सभी लोगों की पहुंच सुरक्षित और पोषक खाद्य तक करने की घोषणा की गई थी और विश्व में खाद्य सुरक्षा का ध्येय रखा गया था। सम्मेलन में सभी देशों से भुखमरी दूर करने का आव्हान किया गया था और वर्ष 2015 तक अल्पपोषितों की संख्या आधी करने की बात कही गई थी, परन्तु हाल की एफ.ए.ओ. की रिपोर्ट के अनुसार अल्पपोषितों की संख्या आधी करने का लक्ष्य 2030 तक भी पूरा होने की आशा नहीं है। वर्ष 2008-09 में हमारा खाद्य उत्पादन 23.0 करोड़ टन होने का अनुमान है जो वर्ष 2007-08 में 23.08 करोड़ टन था। यदि सभी आधे पेट भोजन करने

वाले लोगों को भर पेट भोजन दिया जाए तो इस समय का उत्पादन हमारी लगातार बढ़ रही आबादी के लिए पर्याप्त नहीं होगा। बढ़ती आबादी ने अधिक पैदावार के लाभ को समाप्त कर दिया है और यह हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती है।

खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए मुख्यतः निम्न बातों पर निर्भर होना पड़ेगा - सभी वर्षों में अच्छा मानसून, कृषि के क्षेत्रफल की बढ़ोत्तरी, प्रति हैक्टर पैदावार में वृद्धि तथा वर्षाधीन शुष्क खेती के अंतर्गत उन्नत कृषि आदि। फसली क्षेत्र का दो तिहाई भाग शुष्क खेती में है जिसमें कुल उत्पादन का 42 प्रतिशत खाद्यान्न पैदा होता है। इस क्षेत्र में या तो हम किसी चमत्कारी विदेशी बीज का इंतज़ार करें अथवा बढ़ती आबादी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए खेती की परिस्थितियों के अनुसार अपना ही कोई पैकेज विकसित करें।

तथाकथित गेहूं और चावल की हरित क्रांति अपने चरम पर पहुंच चुकी है। इसने वर्षाधीन क्षेत्रों में और दालों अथवा मोटे अनाज के क्षेत्र में कोई खास बढ़ोत्तरी नहीं दिखाई है। फसलों का क्षेत्र भी ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। हरित क्रान्ति ने कृषि पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पैदा किया है। भूमि, पानी और जैव संसाधनों पर गुणात्मक और मात्रात्मक निम्नीकरण का प्रभाव पड़ा है। पानी के भराव और लवणीकरण के कारण उपजाऊ भूमि बरबाद हुई है। उत्पादकता में कमी आई है और कटाई उपरांत हानियां बहुत अधिक हैं।

चावल और गेहूं की नई विकसित प्रजातियां अपनी अधिकतम सीमा तक पंहुच चुकी हैं। पंजाब और हरियाणा में लवणीयता और पोषक तत्व असंतुलन की समस्या सामने आ गई है तथा सिंचाई प्रभावहीन हो गई है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी चिंताजनक है। फिर भी, पूर्वी उत्तर प्रदेश से असम तक चावल की उत्पादकता में सुधार तथा इस पूर्वी क्षेत्र की क्षमता का पूरी तरह दोहन करने की संभावना है।

आजकल जिनेटिक रूप से परिवर्तित बीजों से खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक दूसरी हरित क्रांति की वकालत की जा रही है। परंतु इस तकनीक का प्रयोग तभी हो सकता है जब यह पूरी तरह से सुरक्षित हो। इसके लिए कुछ वर्षों तक सुरक्षा सम्बंधी परीक्षणों की आवश्यकता है।

विशाल आबादी हेतु खाद्यान्न और पोषण सुनिश्चित करने और भारत को भुखमरी मुक्त बनाने का लक्ष्य एक बड़ी चुनौती है। खास तौर से तब जब पर्याप्त खाद्य उत्पादन होने के बावजूद भी एक तिहाई बच्चे कुपोषित हैं जिसके लिए गरीबी एक मुख्य कारण है। आने वाले 15 वर्षों में अपने खाद्य उत्पादन को दुगना करना ज़रूरी होगा जिसके लिए 4.7 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि आवश्यक होगी। इसके लिए ग्रामीण संसाधन ढांचे तथा बड़ी हानियों को रोकने के पर्याप्त सुधार ज़रूरी हैं। सार्वजनिक वितरण तंत्र और काम के बदले अनाज जैसे कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र में लागू करना होगा और रोज़गार के साधन उपलब्ध कराने होंगे ताकि गरीब किसानों की आमदनी का स्तर बढ़े और वे भोजन की पूर्ति कर सकें। भुखमरी को रोकने के लिए आर्थिक नीतियों में सुधार लाने की भी आवश्यकता है ताकि सबके लिए भोजन का लक्ष्य हासिल किया जा सके। ***(स्रोत फीचर्स)***

स्रोत सजिल्द

वर्ष 2009 के सारे अंक एक जिल्द में उपलब्ध हैं